ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

झारखंड में युवा शिक्षा के सामाजिक–आर्थिक निर्धारकः देवघर जिले का एक केस स्टडी

सुनील कुमार नरौने[1], डॉ0 कुलदीप[2]

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, साई नाथ विश्वविद्यालय[1]

शोध–निर्देशक, शिक्षाशास्त्र विभाग, साई नाथ विश्वविद्यालय[2]

सार

यह शोध पत्र झारखंड राज्य के देवघर जिले में युवाओं की शैक्षिक अनुभवों पर सामाजिक–आर्थिक कारकों के प्रभाव की जांच करता है। यह क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक असमानताओं से प्रभावित एक पिछड़ा इलाका है, जो यह समझने के लिए एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है कि घरेलू आय, माता–पिता की शिक्षा का स्तर, पेशागत पृष्ठभूमि तथा जाति या समुदाय की स्थिति जैसे कारक शैक्षिक परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन सर्वेक्षण–आधारित पद्धति को अपनाता है, जिसमें 15 से 24 वर्ष की आयु के 300 युवाओं से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए। शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता से संबंधित धारणाओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझने के लिए एक संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जो 5–बिंदु वाले लाइकेर्ट स्केल पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल शैक्षिक उपलब्धियों में मात्रात्मक अंतर को ही नहीं, बल्कि युवाओं द्वारा झेली जा रही गुणात्मक चुनौतियोंकृजैसे शिक्षा की वहनीयता, विद्यालय का बुनियादी ढांचा, अभिभावकों की भागीदारी और आकांक्षात्मक बाधाएँकृ को भी उजागर करना है। परिणामों से यह अपेक्षा की जाती है कि निम्न–आय वाले परिवारों और कम शिक्षित माता–पिता अक्सर शैक्षिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति या सीमित शैक्षणिक भागीदारी देखी जाती है। विशेषकर कृषि या असंगठित श्रमिकों की पेशागत भूमिका बच्चों की स्कूली भागीदारी को प्रभावित कर सकती है, जहाँ शिक्षा के बजाय कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

यह अध्ययन यह भी विश्लेषण करता है कि किस प्रकार लिंग और समुदाय–आधारित पहचान आर्थिक स्थिति के साथ मिलकर कुछ वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेल देती है। प्रमुख बाधाओं और सहायक तत्वों की पहचान करके यह शोध पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और गरीबी के संबंध को बेहतर ढंग से समझने में योगदान देने का प्रयास करता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष स्थानीय सरकारी एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों और शैक्षिक योजनाकारों को अधिक समावेशी और प्रभावी नीतियाँ तैयार करने में

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अंततः यह शोध ग्रामीण युवाओं के लिए, विशेष रूप से देवघर जैसे वंचित क्षेत्रों में, समान और सतत शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों की वकालत करता है।

कीवर्ड्स *सामाजिक–आर्थिक स्थिति, युवा शिक्षा, देवघर, झारखंड, ग्रामीण विकास, लाइकेर्ट स्केल, सर्वेक्षण विधि*

1. भूमिका

शिक्षा व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति का एक सशक्त माध्यम है, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह न केवल व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि मानव संसाधन को विकसित करके राष्ट्र की समग्र उन्नति में भी योगदान देती है। हालांकि, भारत जैसे विविधता से भरे देश में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता क्षेत्रों के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति विशेष रूप से कमजोर देखी जाती है। झारखंड राज्य का देवघर जिला इस असमानता का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ ग्रामीण और अर्ध–शहरी आबादी को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्राप्त करने में कई प्रकार की चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं। यद्यपि सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक सरकारी योजनाएँ चलाई गई हैं, फिर भी देवघर में शैक्षिक प्राप्ति में कई सामाजिक–आर्थिक कारक बाधा बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है पारिवारिक आयय निम्न–आय वाले परिवारों के छात्र पुस्तकों, यूनिफॉर्म, परिवहन, ट्यूशन या नियमित उपस्थिति जैसे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना करते हैं। माता–पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक हैय पढ़े–लिखे माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, जबकि अशिक्षित या अल्पशिक्षित माता–पिता इसके दीर्घकालिक लाभों को समझ नहीं पाते।

इसके अतिरिक्त, परिवार की पेशागत पृष्ठभूमिकृविशेषकर वे जो असंगठित, मौसमी या श्रम–प्रधान कार्यों में संलग्न होते हैंकृशैक्षिक निरंतरता को बाधित कर सकती है, क्योंकि ऐसे परिवारों में बच्चों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की जाती है। जाति और समुदाय की पहचान भी शैक्षिक पहुँच को प्रभावित करती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ प्रणालीगत भेदभाव या सामाजिक बहिष्करण की स्थिति अब भी बनी हुई है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि युवा किस स्थान पर रहते हैंकृदूरस्थ गाँवों में या शहरीकरण की ओर बढ़ते कस्बों मेंकृयह भी स्कूलों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की गुणवत्ता और संपूर्ण शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन सभी सामाजिक–आर्थिक चर की संयुक्त भूमिका का विश्लेषण करना है, जो 15 से 24 वर्ष के युवाओं के शैक्षिक अनुभवों को आकार देती है। यह शोध आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारकों के आपसी संबंधों को उजागर करते हुए क्षेत्रीय शैक्षिक विषमता के मूल कारणों को समझने का प्रयास करता है। स्थानीय वास्तविकताओं पर

आधारित एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाकर यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, लक्षित हस्तक्षेपों और शैक्षिक योजनाओं को जानकारीपूर्ण दिशा देने की आकांक्षा रखता है, ताकि देवघर के युवाओं के लिए शिक्षा की खाई को पाटा जा सके और एक अधिक समावेशी भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जा सके।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. देवघर जिले के युवाओं की शैक्षिक प्राप्ति पर सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
2. माता–पिता की पृष्ठभूमि (शिक्षा, पेशा) और युवाओं की स्कूल तथा उच्च शिक्षा तक पहुँच के बीच संबंध को समझना।
3. झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक आकांक्षाओं को बाधित करने वाले विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक अवरोधों की पहचान करना।

3. साहित्य समीक्षा

मार्टिनेज, जे. डी. (2000): घर एक सामाजिक संगठन होता है, जिसकी व्यवस्था परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति करता है और यह परिवार के सदस्यों की आय तथा सामाजिक मानदंडों की स्वीकृति पर आधारित होता है। प्रत्येक घर का वातावरण भिन्न होता है, जिसमें नियंत्रण, संरक्षण, अनुचित प्रतिक्रियाओं पर दंड या सुधार की प्रक्रियाएँ भिन्न होती हैं। इसमें समानता या असमानता, विशेषाधिकार या वंचन, पोषण या अस्वीकृति जैसे तत्व शामिल होते हैं। ये सभी कारक उस पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करते हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है और इसके परिणामस्वरूप मानसिक और शारीरिक स्थिति भी प्रभावित होती है।

आधुनिकीकरण के इस युग में, तनाव, दबाव और अवसाद की स्थिति किशोरों में भी सामान्य होती जा रही है। यह स्थिति छात्रों की पढ़ाई को भी प्रभावित करती है। बच्चे की उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में पारिवारिक वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक परिपक्वता और सामाजिक–आर्थिक स्थिति शामिल हैं। किशोरावस्था अनेक तनावपूर्ण परिस्थितियों से घिरी होती है। कोई भी व्यक्तिकृचाहे वह बच्चा हो या किशोरकृअपना एक विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य रखता है, जो जीवन के प्रति उसके समस्त व्यवहारों में परिलक्षित होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका प्रभावी शिक्षा और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

सुजाता, के. (2002): भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि षशिक्षा का अधिकार अधिनियमष और ष्सर्व शिक्षा अभियानष के माध्यम से उनकी शैक्षिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है। इसके बावजूद जनजातीय समुदाय अब भी किसी न किसी रूप में शैक्षिक वंचना का सामना कर रहे हैं। हालांकि यह वंचना एक समान नहीं है, यह स्थान के अनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, रांची जिले के आदिवासी समुदाय की साक्षरता दर और सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति देवघर जिले के आदिवासियों की तुलना में काफी बेहतर है, जबकि दोनों जिले एक ही राज्यकृझारखंडकृमें स्थित हैं।

इन भिन्नताओं का मुख्य कारण यह है कि इन जनजातीय समूहों को बाहरी दुनिया के साथ पहले कैसा संपर्क रहा है और इनकी शिक्षा में सरकार की भूमिका कैसी रही है। यह अध्ययन झारखंड राज्य के दो गांवों पर आधारित एक अनुभवजन्य शोध है, जिसमें डेटा वर्ष 2007दृ08 में विभिन्न उपकरणों जैसे साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा, नृविधिक विश्लेषण और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें एक गाँव रांची जिले से और दूसरा गाँव देवघर जिले से लिया गया है।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन झारखंड राज्य के देवघर जिले के युवाओं की शैक्षिक वास्तविकताओं की पड़ताल के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति को अपनाता है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक–आर्थिक कारक किस प्रकार युवाओं की शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। अध्ययन के लिए 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 300 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जो देवघर के ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों से लिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना जनसंख्या की विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों का समुचित प्रतिनिधित्व करता है, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना तकनीक का प्रयोग किया गया। डेटा संग्रह हेतु एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें प्रतिभागियों की धारणाओं को समझने के लिए 5–बिंदु वाली लाइकेर्ट स्केल को शामिल किया गया। प्रश्नावली तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थीरू घरेलू आय, माता–पिता की शिक्षा, और सामाजिक पृष्ठभूमि का शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता पर प्रभाव। इस उपकरण के माध्यम से प्राप्त उत्तरों ने सामाजिक–आर्थिक आयामों के प्रभाव को लेकर व्यक्तिपरक समझ और मापनीय दोनों प्रकार के आंकड़े प्रदान किए।

संग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों से किया गया। गुणात्मक विश्लेषण में प्रतिभागियों के खुले उत्तरों से उभरने वाले प्रमुख विषयों और प्रवृत्तियों की पहचान की गई, जिससे निष्कर्षों को संदर्भगत गहराई प्राप्त हुई। वहीं, मात्रात्मक विश्लेषण में औसत स्कोर और सहमति का प्रतिशत जैसे वर्णनात्मक आँकड़ों का प्रयोग किया गया, जिससे उत्तरदाताओं के बीच प्रचलित

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

प्रवृत्तियों और सामान्य धारणाओं की पहचान की जा सकी। इस मिश्रित विधिक दृष्टिकोण ने देवघर के युवाओं की शिक्षा में बाधाओं और सहायक तत्वों की व्यापक समझ प्रदान की।

5. डेटा विश्लेषण

तालिका 1 मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति ने मेरी शिक्षा जारी रखने की क्षमता को प्रभावित किया है।

कथन	संख्या	प्रतिशत
दृढ़तापूर्वक सहमत	84	28.0
सहमत	102	34.0
तटस्थ	54	18.0
क्पेंहतमम	36	12.0
दृढ़तापूर्वक असहमत	24	8.0
कुल	300	100.0

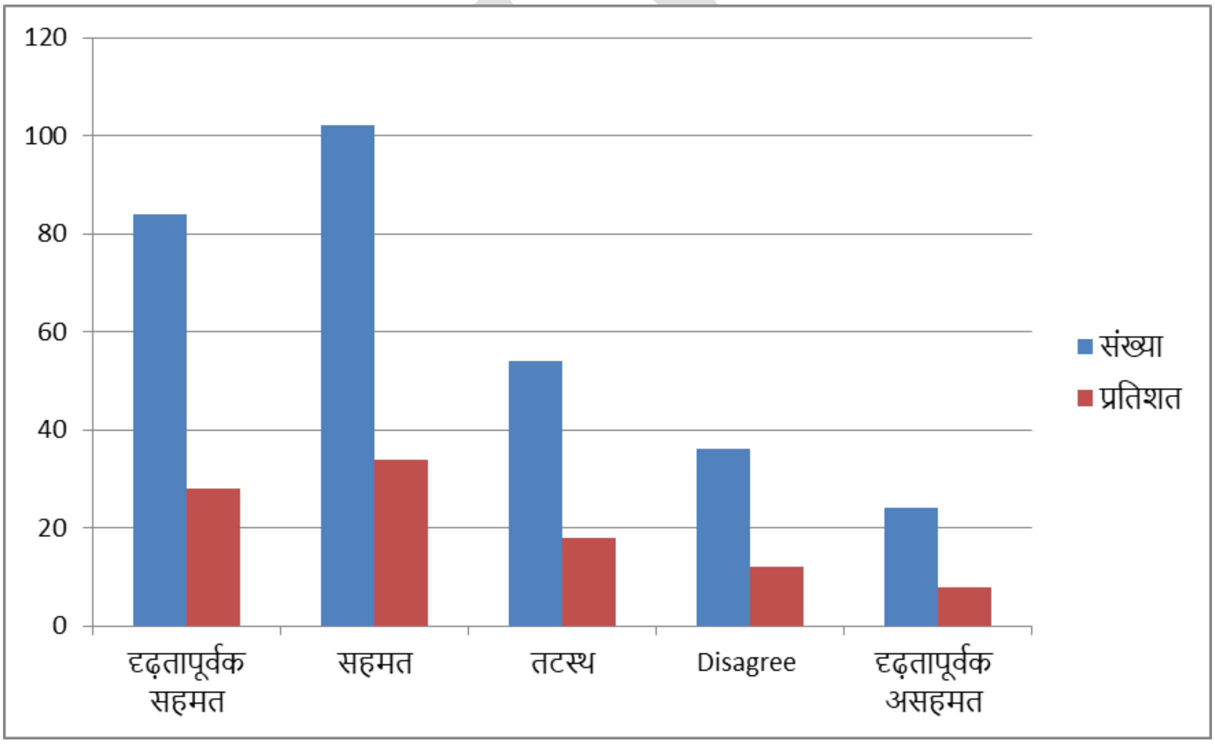

चित्र 1 मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति ने मेरी शिक्षा जारी रखने की क्षमता को प्रभावित किया है।

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

तालिका 2 मेरे माता–पिता की शिक्षा का स्तर घर पर मेरी पढ़ाई को दिए जाने वाले महत्व को प्रभावित करता है।

कथन	संख्या	प्रतिशत
दृढ़तापूर्वक सहमत	75	25.0
सहमत	90	30.0
तटस्थ	60	20.0
क्पेंहतमम	45	15.0
दृढ़तापूर्वक असहमत	30	10.0
कुल	**300**	**100.0**

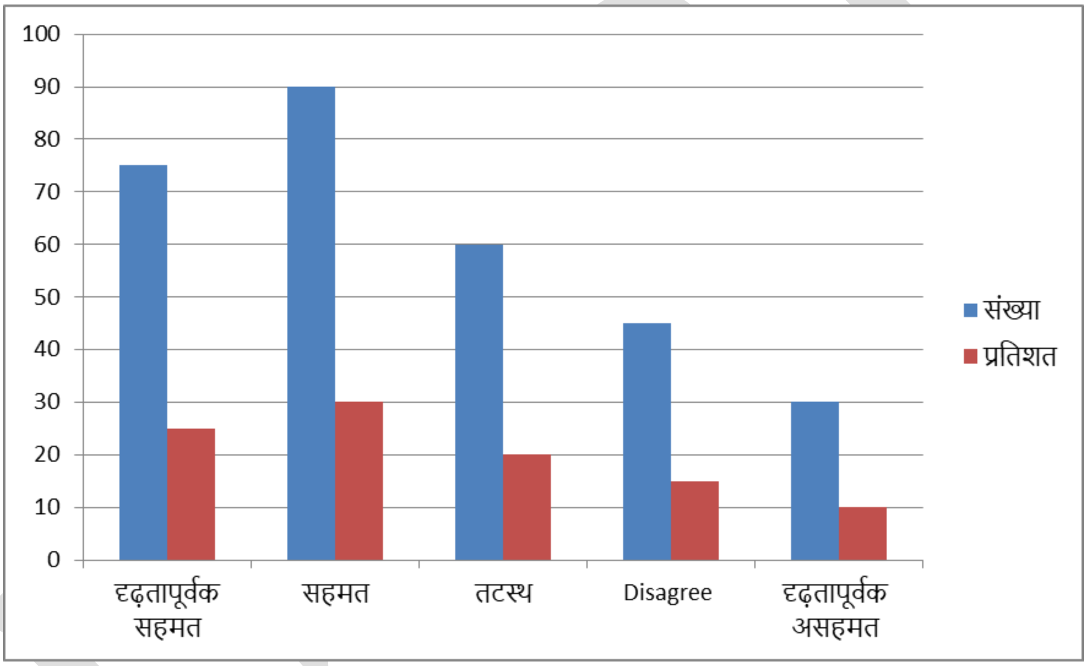

चित्र 2 मेरे माता–पिता की शिक्षा का स्तर घर पर मेरी पढ़ाई को दिए जाने वाले महत्व को प्रभावित करता है।

तालिका 3 मेरे माता–पिता/अभिभावकों का व्यवसाय मेरे शैक्षिक लक्ष्यों और अपेक्षाओं को प्रभावित करता है।

कथन	संख्या	प्रतिशत
दृढ़तापूर्वक सहमत	80	26.7
सहमत	95	31.7

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

तटस्थ	60	20.0
क्पेंहतमम	40	13.3
दृढ़तापूर्वक असहमत	25	8.3
कुल	**300**	**100.0**

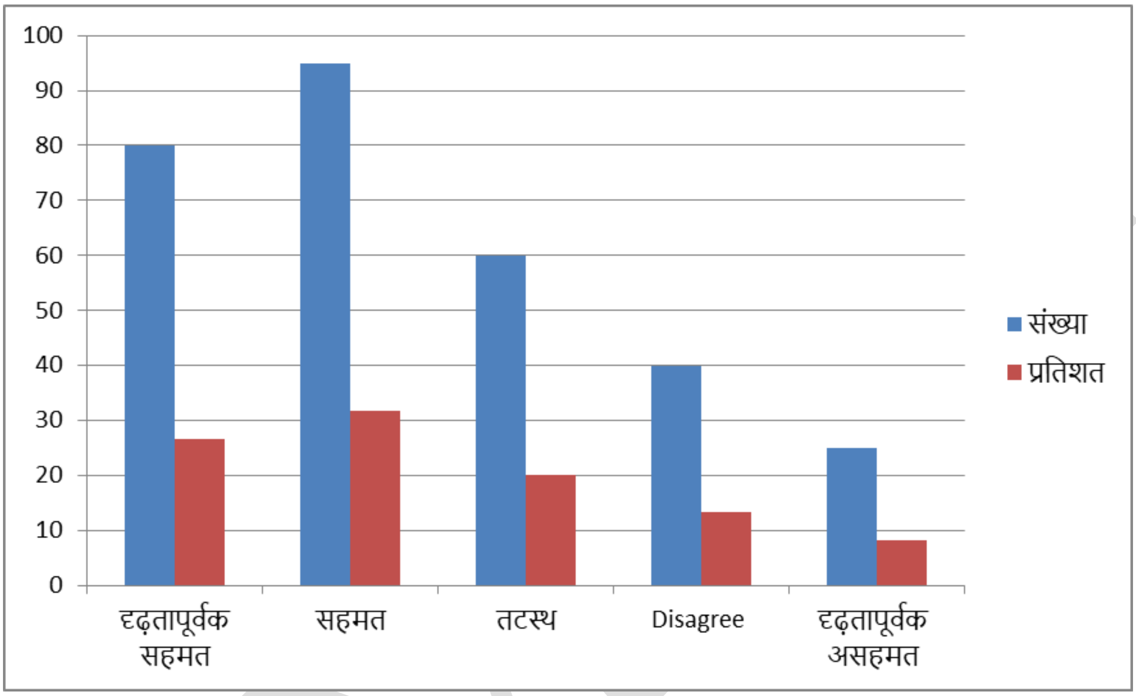

चित्र 3 मेरे माता–पिता/अभिभावकों का व्यवसाय मेरे शैक्षिक लक्ष्यों और अपेक्षाओं को प्रभावित करता है।

तालिका 1, 2 और 3 में प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारक झारखंड के देवघर जिले के युवाओं के शैक्षिक अनुभवों और आकांक्षाओं को आकार देते हैं।

तालिका 1 में यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कृ कुल 62ः कृ इस बात से सहमत है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने और जारी रखने की क्षमता को प्रभावित किया है (28ः पूरी तरह सहमत, 34ः सहमत)। यह संकेत देता है कि आर्थिक कठिनाइयाँ इस क्षेत्र के छात्रों के लिए एक प्रमुख बाधा हैं, जो उन्हें ट्यूशन, किताबें, परिवहन, और डिजिटल उपकरण जैसी आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच से वंचित कर देती हैं। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार मौसमी या कम वेतन वाली नौकरियों पर निर्भर हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या शिक्षा की लागत वहन न कर पाने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते।

ISSN: 2249-7196

IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452

सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

तालिका 2 में माता–पिता की शिक्षा का युवाओं की पढ़ाई पर प्रभाव उजागर होता है। यहाँ 55ः उत्तरदाताओं (25ः पूरी तरह सहमत, 30ः सहमत) का मानना है कि उनके माता–पिता की शैक्षिक योग्यता घर में शिक्षा को दी जाने वाली प्राथमिकता को प्रभावित करती है। उच्च शिक्षित माता–पिता न केवल सीखने को महत्व देते हैं बल्कि बच्चों को मार्गदर्शन और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, जिन घरों में माता–पिता की शिक्षा सीमित है, वहाँ बच्चों की शैक्षिक जरूरतों की समझ और समर्थन की कमी पाई जाती है, जिससे उच्च शिक्षा के प्रति अपेक्षाएँ कम हो जाती हैं। इस तथ्य से यह आवश्यकता उजागर होती है कि ऐसे माता–पिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ जो उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराएँ, चाहे उनकी अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

तालिका 3 के आंकड़े बताते हैं कि 58.4ः युवा उत्तरदाता (26.7ः पूरी तरह सहमत, 31.7ः सहमत) मानते हैं कि उनके माता–पिता या अभिभावकों का पेशा उनकी शैक्षिक अपेक्षाओं और लक्ष्यों को प्रभावित करता है। जिन परिवारों के सदस्य श्रम–प्रधान, अनौपचारिक या कम वेतन वाले कार्यों में लगे होते हैं, उनके पास न तो समय होता है और न ही संसाधन कि वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग दे सकें। साथ ही, ऐसे परिवारों के बच्चे आर्थिक असुरक्षा का प्रारंभिक अनुभव कर लेते हैं, जिससे उनमें आगे की शिक्षा के प्रति रुचि कम हो जाती है या वे भी वही पेशा अपनाने को बाध्य हो जाते हैं। इसके विपरीत, जिनके माता–पिता पेशेवर या स्थिर कार्यों में लगे हैं, उनके बच्चे शिक्षा के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं और उच्च शिक्षा की आकांक्षाएँ रखते हैं।

इन तीनों तालिकाओं में, भले ही कुछ उत्तरदाता तटस्थ या असहमत भी हैं, फिर भी समग्र प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आर्थिक स्थिति, माता–पिता की शिक्षा और उनका पेशा शिक्षा की पहुँच और प्रेरणा से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कारक मिलकर कई युवाओं के लिए एक ष्संचयी असमानताष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे नामांकन, अध्ययन में निरंतरता, प्रदर्शन और आकांक्षाओं में असमानता पैदा होती है। इसलिए, देवघर जैसे जिलों में शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार लक्षित नीतियाँ बनाए, जैसे कि आर्थिक सहायता योजनाएँ, माता–पिता को जागरूक करने वाले कार्यक्रम, और समावेशी कौशल–आधारित शिक्षा के रास्ते। ये प्रयास सामाजिक–आर्थिक बहिष्करण के चक्र को तोड़ने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

6. निष्कर्ष

यह केस स्टडी दर्शाती है कि देवघर में युवाओं की शिक्षा क्षेत्र की व्यापक सामाजिक–आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। शोध निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आर्थिक तंगी, माता–पिता की कम शैक्षिक योग्यता, जाति आधारित असमानताएँ और जागरूकता की कमी ग्रामीण युवाओं की शैक्षिक

ISSN: 2249-7196
IJMRR/Oct.- 2023/ Volume 13/Issue 3/443-452
सुनील कुमार नरैने/ International Journal of Management Research & Review

उपलब्धियों में प्रमुख बाधाएँ हैं। ये चुनौतियाँ न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच को सीमित करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन में निरंतरता, प्रदर्शन और उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं को भी प्रभावित करती हैं। इन प्रणालीगत समस्याओं को हल करने के लिए एक बहु–आयामी रणनीति आवश्यक है। प्रथम, वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति और शर्त–आधारित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और स्कूली उपस्थिति को प्रोत्साहन मिले। द्वितीय, समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से कम शिक्षित माता–पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। तृतीय, स्कूल प्रणाली में कौशल–आधारित और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम को एकीकृत करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और रोजगार से जुड़ी हो सके, और इस प्रकार यह छात्रों व उनके परिवारों दोनों के लिए अधिक आकर्षक बन सके।

इसके अतिरिक्त, नीतिगत हस्तक्षेपों को ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक आधारभूत संरचना की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें बेहतर शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल शिक्षण संसाधन, और समावेशी विद्यालय वातावरण की व्यवस्था शामिल है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, स्थानीय शासन संस्थाओं को सशक्त बनाना और समुदाय के हितधारकों को शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करना एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जो शिक्षा को सामाजिक उन्नयन के माध्यम के रूप में देखती है। अतः, देवघर में युवा शिक्षा में सुधार केवल एक शैक्षिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता है, जिसे स्थायी विकास और पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. चोपड़ा, डी. (2015)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारतरू परिवर्तनकारी सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मार्गों की जांच (पृष्ठ 1–40)। विकास अध्ययन संस्थान।
2. ड्रेज, जे., और खेरा, आर. (2017)। भारत में हाल की सामाजिक सुरक्षा पहल। विश्व विकास, 98, 555–572। ीजजचेरूध्धकवप.वतहध10.1016ध्र.वतसककमअ.2017.05.035
3. खेरा, आर. (2011)। महिला श्रमिक और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारणाएँ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 46(43), 49–57।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2022)। वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 (पृष्ठ 20–110)। भारत सरकार।
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2021)। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दिशानिर्देश (पृष्ठ 5–60)। भारत सरकार।

6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। (2019)। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018—19 (पृष्ठ 1—88)। भारत सरकार।

7. सिंह, आर. (2020)। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का मूल्यांकनरू मनरेगा और डीडीयू—जीकेवाई का तुलनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, 12(3), 45—58।

8. बसोले, ए., और जयदेव, ए. (2019)। ग्रामीण भारत में रोजगार पैटर्न। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 54(42), 23—29।

9. रेड्डी, डी. एन., और श्रीजा, ए. (2016)। भारत में कौशल विकासरू चुनौतियाँ और अवसर। योजना, 60(4), 45—49।

10. देसाई, एम. (2003)। भारत में सार्वजनिक कार्य और रोजगार कार्यक्रम। एम. दासगुप्ता (एड.), गरीबी और सामाजिक विकास (पृष्ठ 123—135) में। मैकमिलन इंडिया।

11. अमर्त्य सेन. (1999)। विकास स्वतंत्रता के रूप में (पृष्ठ 87—120)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

12. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (2020)। मानव विकास रिपोर्ट 2020रू अगला मोर्चा—मानव विकास और एंथ्रोपोसीन (पृष्ठ 45—72)। यूएनडीपी।

13. देव, एस. एम. (2018)। ग्रामीण भारत का परिवर्तनरू चुनौतियाँ और अवसर। भारतीय मानव विकास जर्नल, 12(3), 311—328।

14. जाटव, एम., और सेन, एस. (2013)। रोजगार गारंटी और पलायनरू राजस्थान में मनरेगा का प्रभाव मूल्यांकन। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 1(1), 31—48।

IJMRR